पहले पेज से आगे

यूपी में कई बड़े अफसरों पर आयकर छापे

उस समय घर पर विमल कुमार शर्मा के भाई डा. वीके शर्मा तथा शरद शर्मा मौजूद थे। इस दौरान उनसे मिलने आए भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष राजेंद्र सोनी को भी आयकर विभाग की टीम ने बाहर जाने से रोक दिया। ये कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक जारी रही। कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग की टीम के अधिकारियों ने न तो घर से किसी को बाहर जाने दिया और न ही किसी को बाहर से अंदर आने दिया। कार्रवाई को लेकर किसी भी अधिकारी ने कोई बयान नहीं दिया।

जानकारी के मुताबिक इस यह कार्रवाई मैनपुरी आयकर विभाग के प्रभारी आयकर अधिकारी अनिल कुमार पटेल के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई के दौरान विमल कुमार के घर के बाहर बनी दुकानों को किराए पर लिए दुकानदारों को भी बुलाकर पूछताछ की गई। माना जा रहा है कि विभाग के अधिकारियों ने इनके बयान नोट किए हैं।

टीम ने दुकानदार प्रमोद कुमार गुप्ता व अलाउद्दीन मंसूरी से पूछताछ की है। ये कार्रवाई क्यों की गई इसका भी अभी तक जवाब नहीं मिल सका है। लेकिन बताया जा रहा है कि विमल कुमार शर्मा से जुड़े सभी ठिकानों पर आयकर विभाग ने एक साथ ये कार्रवाई की है। विमल कुमार शर्मा वर्तमान में नोएडा प्राधिकरण में एडीशनल सीईओ पद पर तैनात हैं। इनकी पत्नी ममता शर्मा मेरठ में आरटीओ हैं। यहां पर भी आयकर की टीम ने छापा मारा है।

डा. विमल कुमार शर्मा गाजियाबाद और फिरोजाबाद के जिलाधिकारी रह चुके हैं। इसके अलावा वे शासन के कई महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती पा चुके हैं। जानकारी तो ये भी है कि डॉ. विमल कुमार शर्मा के मेरठ, आगरा और गाजियाबाद स्थित आवासों पर भी आयकर विभाग की टीमों ने कार्रवाई की है। आयकर की ये कार्रवाई बेहद गुप्त रूप से की गई। इस कार्रवाई की किसी को भनक तक नहीं लगी। अचानक सुबह जब आयकर विभाग के अधिकारियों की गाड़ियां भोगांव विमल कुमार शर्मा के घर पहुंची तो पहले तो किसी को अंदाजा ही नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब लोगों को पता चला कि ये छापामार कार्रवाई है तो हड़कंप मच गया। लोग जमा हो गए।

सीआरपीएफ के पूर्व आईजी को कनाडा से वीजा न

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जैसे एक प्रतिष्ठित बल के इस तरह के वर्णन को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। बागले ने कहा कि हमने एक वरिष्ठ सेवानिवृत भारतीय पुलिस अधिकारी को कनाडाई अधिकारियों द्वारा प्रवेश से मना करने के बारे में खबरें देखी हैं। हम कनाडा सरकार के समक्ष यह मुद्दा ले गए हैं। वहीं, कनाडा के उच्चायुक्त नादिर पटेल ने एक बयान में कहा कि हवाईअड्डा पर ढिल्लन को दिए गए एक दस्तावेज में मौजूद भाषा भारत या सीआरपीएफ सहित किसी खास संगठन के प्रति कनाडा सरकार की नीति को जाहिर नहीं करती। बल भारत में कानून व्यवस्था कायम रखने में एक अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने, ढिल्लन और उनके परिवार को हुई किसी भी असुविधा को लेकर खेद प्रकट किया। ढिल्लन 2010 में बल के आईजी पद से सेवानिवृत्त हुए थे।

एक फर्जी मुठभेड़ की-सीआरपीएफ आईजी

राय ने अपने पत्र में यह भी दावा किया है कि इस घटना के चश्मदीद गवाह उनके पास अब भी सुरक्षित हाल में हैं। इन गवाहों ने दोनों युवकों को पकड़कर ले जाते हुए देखा था। बाद में मारे जाने के बाद इन्हीं गवाहों ने उन युवकों की शिनाख्त भी की थी। राय ने यह पत्र 17 अप्रैल को लिखा था। इसकी प्रति उन्होंने असम के मुख्य सचिव वीके पिपरसेनिया को भी भेजी है।

खुदकुशी को निकली

मंदिर में शादी कर ली थी ताकि कोई उनके ऊपर सवाल न खड़ा कर सके। हालांकि दोनों की शादी अंतरजातीय है। कुछ लोगों ने इस बात को भी मुद्दा बनाने की कोशिश की है, लेकिन अखिलेश के परिजनों का इसका कोई असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं कुछ लोग पिंकी और अखिलेश के फैसले की तारीफ भी कर रहे हैं उनका कहना है कि पिंकी ने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर बहुत अच्छा किया है।

शीना हत्या

साल 2012 में शीना की हत्या कर दी गई थी। उसका शव जंगल में ले जाकर दफनाने की कोशिश की गई थी। इस मामले में इंद्राणी के पूर्व पति और ड्राइवर भी आरोपी हैं। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है।

तेजाबी हमला, 17 सर्जरी के बाद शादी

राहुल ने गलती से ललिता को फोन लगा दिया था और दोनों लोगों ने दो महीने बाद ही यह फैसला कर लिया कि वे शादी करेंगे।

ललिता इतनी खुश हैं कि कहती हैं- सोचा नहीं था कभी शादी होगी। उन्हें सच्चाई पता चल गई थी लेकिन फिर भी वह मुझसे शादी के फैसले पर कायम रहे। मुंबई के मलाड में राहुल सीसीटीवी ऑपरेटर के तौर पर काम करते हैं। कहते हैं कि इस फैसले में मां समेत मेरे पूरे परिवार ने मेरा साथ दिया। ललिता के रिहैबिलिटेशन का लेकर साहस नामक एनजीओ उत्साहित है। एक्टर विवेक ओबरॉय ने ललिता को ठाणे में फ्लैट बतौर तोहफा दिया है। डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला ने ललिता का विवाह का जोड़ा तैयार किया है और तोहफे में नेकलेस दिया है।

विवेक ओबरॉय ने कहा कि वह ललिता से एक अवेयरनेस प्रोग्राम में मिले थे। उन्होंने इस जोड़े को शुभकामनाएं दीं और कहा-ललिता मजबूत लड़की है और राहुल उनसे सच्चा प्यार करते हैं।

पेज 12 से आगे

नांदगांव जिले में 91 हजार को उज्ज्वला गैस कनेक्शन

इससे पहले मुख्यमंत्री ने खैरागढ़ विकासखंड के ग्राम ठेलकाडीह में छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 175 करोड़ की लागत से 19.43 कि.मी. लंबाई के ढारा-ठेलकाडीह मार्ग, 15.89 कि.मी. लंबाई के चिखली-पदुमतरा मार्ग, 20.01 कि.मी. लंबाई के जी.ई. रोड-इंदामारा-ठेलकाडीह मार्ग के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने ग्राम ठेलकाडी और आस-पास के गांवों में पानी की किल्लत दूर करने के लिए 20.87 करोड़ की लागत से सोलर पंपों की स्थापना के कार्य का शिलान्यास किया। इसके साथ ही डॉ. सिंह ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 5 हितग्राहियों को गैस चूल्हा, प्रधानमंत्री खरीफ फसल योजना के तहत 6 कृषकों को क्षतिपूर्ति राशि, आत्मा योजना के तीन हितग्राहियों को चेक और प्रमाण पत्र प्रदान किये।

मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने ग्राम ठेलकाडीह के ग्रामीणों को संबोधित करते कहा कि तीनों सड़कों का आज भूमिपूजन किया गया है और इनका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। जिससे यहां के ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि जिले में अब तक 91 हजार महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन प्रदान किये जा चुके है। डॉ. सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उज्ज्वला योजना के लिए आभार जताया और कहा कि प्रधानमंत्री जी ने भाई की हैसियत से देश की महिलाओं को बहन मानते हुए उज्ज्वला योजना शुरू की है। डॉ. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 हजार आवासों के निर्माण की स्वीकृति मिल गई है और जल्द ही निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायेगा। जिसके बाद कोई भी आवास विहीन परिवार खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि ग्राम ठेलकाडीह और आसपास के गांवों में पानी की बहुत किल्लत थी, लेकिन अब यहां के लोगों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ठेलकाडीह समूह जल प्रदाय योजना के तहत खैरागढ़ विकासखंड के 41 ग्राम, डोंगरगढ़ के 23 ग्राम एवं राजनांदगांव के 27 ग्रामों सहित कुल 151 ग्रामों में सोलर पंप स्थापना का कार्य शीघ्र ही शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विकासखंड राजनांदगांव के 65 ग्रामों में 75 नग, खैरागढ़ के 28 ग्रामों में 30 नग एवं डोंगरगढ़ के 16 ग्रामों में 16 नग इस प्रकार कुल 109 ग्रामों में 121 सोलर पंपों की स्थापना कार्य हेतु कार्यादेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने भीषण गर्मी के बावजूद समारोह में भारी संख्या में आये ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में राजनांदगांव के सांसद अभिषेक सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जिले के विकास के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि तीनों सड़कों के बन जाने से यहां की जनता के लिए आवागमन सुलभ हो जायेगा, साथ ही सोलर पंपों की स्थापना से पानी की समस्या भी दूर होगी। ठेलकाडीह कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष चित्रलेखा वर्मा, डोंगरगढ़ विधायक सरोजनी बंजारे, कलेक्टर मुकेश बंसल, पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल, छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक अनिल राय, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष सचिन बघेल, राज्य भण्डार गृह निगम के अध्यक्ष नीलू शर्मा, जनपद अध्यक्ष खैरागढ़ विक्रांत सिंह, पूर्व विधायक कोमल जंघेल, संतोष अग्रवाल एवं जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से संक्षिप्त चर्चा में उन्होंने कहा कि राजनांदगांव जिला विकास के शिखर पर पहुंच रहा है। सड़क निर्माण करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। महाराष्ट्र सीमा में बसा यह इलाका अब सड़कों से अभाव से दूर रहेगा। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि आज दो बड़े आयोजन में उमड़ी भीड़ सरकार के बेहतर काम का प्रतिफल है। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत, सांसद अभिषेक सिंह, पद्मश्री फूलबासन यादव, पूर्व मंत्री रजिंदरपाल सिंह भाटिया समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

स्मार्ट सिटी...

विशेषज्ञ अपनी राय देंगे। इसके बाद उनकी राय पर योजनाबद्ध ढंग से विकास के काम कराए जाएंगे। पेयजल, सड़क, बिजली, सफाई, सालिड वेस्ट मैनेजमेट समेत कई काम पीपीपी मोड पर व्यवस्थित ढंग से कराए जाएंगे। कार्यक्रम में विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि रायपुर शहर का तेजी के साथ विकास हो रहा है। 272 करोड़ की लागत से एक्सप्रेस-वे बनाया जा रहा है। बाजारों में पार्किंग की सुविधाएं दी जा रही है। पेयजल, सड़क, बिजली की समस्याओं को दूर करते हुए नई योजनाएं बनायी जा रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई वार्ड खुले में शौचमुक्त बनाए गए। तीन माह में कई झुग्गी बस्तियों को हटाकर 15 सौ गरीबों को पक्के मकान दिए गए। पीएम आवास योजना के तहत आवास निर्माण के काम भी कराए जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सम्मेलन स्मार्ट सिटी की दिशा में अच्छे परिणाम लेकर आएगा।

कार्यक्रम में महापौर प्रमोद दुबे, निगम आयुक्त रजत बंसल, अविनाश ग्रुप के एमडी आनंद सिंघानिया ने भी स्मार्ट सिटी को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। सम्मेलन में आज शाम मुख्यमंत्री डॉ. रमनसिंह व 26 मई को शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू, इस्पात-खान राज्य मंत्री विष्णु देव साय भी शामिल होंगे।

ट्रैफिक पुलिस अब दिन भर भेजेगी अपनी सेल्फी

और स्मार्टफोन को बड़ी मुश्किल से चला पाता हूं। मैं कभी ढंग से सेल्फी नहीं ले पाता।कुछ ट्रैफिक पुलिसवालों ने इस बात को माना भी है कि वे कभी-कभी वॉकी-टॉकी डिवाइसेज पर गलत लोकेशन भी बताते हैं। एक ऑफिसर ने कहा, कभी-कभी हम जब अपनी ड्यूटी पर पहुंचने वाले होते हैं तो फोन पर कहते हैं कि हम ड्यूटी पर पहुंच गए हैं या बस पहुंचने ही वाले हैं लेकिन हम सभी इस बात को जानते हैं कि सुबह के समय में ट्रैफिक प्रॉब्लम सीरियस होती है और हम समय से स्पॉट पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप हम पर संदेह करेंगे। इस तरह टेक गैजट्स की निगरानी ऑफिसर्स को डिमोटिवेट करती हैं और ऐसा करना फोर्स के मनोबल के के लिए अच्छा नहीं है।

पेज 9 से आगे

जनाधार खिसकने के डर से सहारनपुर पहुंचीं मायावती

और न वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था इसके पक्ष में है। पूंजीवाद भी यहाँ सम्पूर्ण रूप से नहीं आया है, और जो है, वह हिन्दू पूंजीवाद है, जिसका सामंतवाद से गठजोड़ है।

यह स्थिति भारतीय लोकतंत्र को ब्राह्मणवाद से ग्रस्त करती है, और ऐसा लोकतंत्र कभी अल्पसंख्यकों के हित में नहीं हो सकता। इसलिए वर्गीय राजनीति का रास्ता सही होते हुए भी दलितों को ब्राह्मणवाद के खिलाफ सीधी लड़ाई का पहला रास्ता ही रास आता है।

लेकिन क्या यह सामाजिक लड़ाई का रास्ता है? मेरा उत्तर हाँ में है। पर वर्तमान में जो सामाजिक आंदोलन दलितों में चल रहे हैं, वे अधिकतर दलितों को भटकाते हैं। वे दलितों में हिन्दूकरण की प्रक्रिया को रोकने में कोई भूमिका नहीं निभाते, बल्कि उनको मुद्दों से भटका कर आरक्षण, और आर्य-अनार्य के इतिहास में उलझाकर रखते हैं।

लेकिन जब चुनाव आते हैं, तो सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा ही उनके सामने विकल्प होते हैं। तब वे बिखर जाते हैं। उनमें से अधिकांश अपनी हिन्दू चेतना के कारण मुसलमानों के खिलाफ हो जाते हैं और भाजपा जैसी हिन्दू पार्टियों को वोट देते हैं।

आर्य-अनार्य की धारा वाले दलित बसपा को पसंद करते हैं। पर जब उनके चुने हुए नेता उनके उत्पीड़न में उनके साथ खड़े नहीं होते हैं, तो वे अपने को ठगा सा पाते हैं। इसीलिए आज अधिकांश दलित नेता भाजपा के साथ हैं, और सवर्णों के खिलाफ नहीं हैं।

इसी तरह मायावती भी भाजपा की विरोधी हैं, पर सवर्णों के खिलाफ नहीं हैं। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दलित जातियों के 80 विधायक हैं, जो आरक्षित सीटों से जीतकर आए हैं।

वे सब के सब सहारनपुर की घटना पर मुंह में दही जमाए बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें दलित प्रेम नहीं है। उनमें प्रेम है, पर यह पूना पैक्ट का दुष्परिणाम है कि वे दलितों के प्रति उत्तरदायी नहीं रह सकते?

यही वह मूल प्रश्न है, जिसके प्रति किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। कांग्रेस ने दलितों को आरक्षित सीटों की रियायतें देकर हिन्दुओं का चमचा बनाने के लिए पूना पैक्ट किया था। और बहुत सुनियोजित तरीके से दलितों के लिए सुरक्षित निर्वाचन के लिए मुस्लिम या सवर्ण बहुल क्षेत्रों को चुना था।

आज जो दलित नेता भाजपा के साथ चले गए हैं, वे अगर वहाँ नहीं जाते, तो अपने समुदाय के वोटों पर अपनी जमानत भी नहीं बचा पाते। वे आज सदन में हैं, तो हिन्दुओं के वोटों से हैं। फिर उनसे दलितों के प्रति उत्तरदायी होने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है?

ब्राह्मणवाद के खिलाफ चिल्लाने वाला कोई भी दलित नेता, राजनीति में आने पर, अपने समुदाय के बल पर नगरपालिका का चुनाव भी नहीं जीत सकता। यही कारण है कि दलित राजनीति दलितों के प्रति उत्तरदायी नहीं बनी रह सकती।

क्या भीम आर्मी के पास इसका कोई विकल्प है? यदि भीम आर्मी को सचमुच क्रान्ति करनी है, तो उसे हिन्दूराष्ट्र तथा ब्राह्मणवाद के विरुद्ध पृथक निर्वाचन की मांग को अपना हथियार बनाना होगा और डॉ. आंबेडकर की हारी हुई लड़ाई को फिर से लड़ना होगा।

यही वह लड़ाई है, जो हिन्दू राष्ट्रवाद को चुनौती दे सकती है। जब तक दलितों के वोटों से दलित प्रतिनिधि नहीं चुने जाएंगे, तब तक दलित राजनीति को दलितों के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता।

सैंडल पहन जीती 50 किमी की रेस

इस सैंडल के अलावा मारिया ने रेस के लिए स्कर्ट और स्कार्फ पहन रखी थी। उन्हें कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं मिली है।

सात घंटे तीन मिनट में मारिया ने ये रेस पूरी की और इनाम के तौर पर उन्हें 320 डॉलर या तकरीबन 20 हजार रुपए दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक मारिया बकरियां और पालतू पशु चराती हैं। हर रोज 10-15 किलोमीटर पैदल चलती हैं। पिछले साल चिहुआहुआ में आयोजित किए गए 100 किलोमीटर की रेस में मारिया दूसरे नंबर पर रही थीं।

मप्र कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन की

इस आधार पर किसी को अचरज नहीं होगा, अगर उन्हें लोकसभा में पार्टी संसदीय दल का नेता भी बना दिया जाए। वहीं, अगर सिंधिया को प्रदेश की कमान सौंपी जाती है तो कमलनाथ को पार्टी संसदीय दल का नेता बनाया जा सकता है।

हालांकि इसी में पेंच ये भी है कि कमलनाथ और सिंधिया दोनों चाहते हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश में पार्टी मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दे। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से सांसद कमलनाथ का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पहले 1980 में सामने आया था। लेकिन उस वक्त पार्टी ने आदिवासी नेता शिवभान सिंह सोलंकी को आगे कर दिया। इसके बाद 1993 में फिर कमलनाथ को दिग्विजय सिंह के लिए पीछे हटना पड़ा। साल 2008 में छिंदवाड़ा में पार्टी सम्मेलन आयोजित कर उन्होंने फिर दावेदारी जताई। लेकिन पार्टी चुनाव नहीं जीत सकी।

लेकिन अब जबकि भाजपा को प्रदेश की सत्ता में 15 साल होने जा रहे हैं, तो कमलनाथ को लग रहा है कि उनके लिए यह एक मौका हो सकता है। लिहाजा कहा जा रहा है कि वे पार्टी नेतृत्व पर दबाव बढ़ाने की रणनीति आजमा रहे हैं। संभवत: इसी के तहत अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में ये खबरें आईं कि कमलनाथ भाजपा में जा रहे हैं। वे उस वक्त भाजपा में तो नहीं गए, अमरीका जरूर चले गए और उनके पीछे कांग्रेस को इस खबर का खंडन करना पड़ा। पार्टी के सूत्र सत्याग्रह से बातचीत में मानते हैं कि कमलनाथ की रणनीति ठीक वैसी ही है, जैसे पंजाब में अमरिंदर ने आजमाई थी। यानी पार्टी छोड़ने की धमकी देकर खुद को प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कराना।

दूसरी तरफ, सिंधिया अलग रणनीति पर चलते नजर आ रहे हैं। खबरों की मानें तो वे पार्टी नेतृत्व को सुझाव दे सकते हैं कि लोकसभा में संसदीय दल के नेता के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति कमलनाथ हो सकते हैं। क्योंकि उनके पास चार दशक से ज्यादा का संसदीय अनुभव है। वे विभिन्न सरकारों में मंत्री रहे हैं लिहाजा मौजूदा सरकार को ज्यादा प्रभावी तरीके से विभिन्न मुद्दों पर घेर सकते हैं। इसके अलावा सिंधिया ने प्रदेश में भी अपनी सक्रियता बढ़ाई है। ताकि कोई भी निर्णय लेने से पहले राज्य की जनता से उनके जीवंत संपर्क का मसला नेतृत्व के जेहन में जरूर आए क्योंकि अन्य नेताओं की तुलना में कमलनाथ की प्रदेश में कम सक्रियता सबके ध्यान में है ही।

2. कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष और सिंधिया मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी बनाए जाएं

दूसरी संभावना ये बनती है कि कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। साथ ही सिंधिया को प्रचार अभियान समिति का प्रमुख या मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया जाए। हालांकि, यह संभावना तभी पूरी तरह सच हो सकेगी, जब खुद कमलनाथ इसके लिए राजी हों। सिंधिया के समर्थकों में शुमार होने वाले पार्टी के एक नेता सत्याग्रह से बातचीत में कहते हैं, कमलनाथजी 72 साल के हो चुके हैं। उनके पास अनुभव है। पार्टी में उनका सम्मान है। उनके नाम पर सब लोग एक साथ एकजुट भी हो जाएंगे। वे कहेंगे तो खुद सिंधिया भी उनके लिए दावेदारी छोड़ देंगे। लेकिन उन्हें इस वास्तविकता को स्वीकार भी कर लेना चाहिए कि आम जनता और कार्यकर्ताओं से जीवंत संपर्क स्थापित करने के लिए जितनी मेहनत सिंधिया कर सकते हैं, उतनी वे नहीं कर पाएंगे।

उनके मुताबिक, सिंधिया की अपील पूरे प्रदेश युवाओं में है। उनके सामने आने से पार्टी कार्यकर्ताओं में भी नया जोश भरेगा। साल 2013 में उन्हें मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं बनाया गया था। उन्हें चुनाव के लिए बनाई गईं आठ समितियों में से एक- प्रचार अभियान समिति की जिम्मेदारी मात्र दी गई थी। लेकिन तब भी सिंधिया ने जो मेहनत की, उसकी छाप कार्यकर्ताओं के दिमाग में अब तक कायम है। अटेर सहित पिछले कुछ समय में हुए उपचुनाव में उन्होंने जो मेहनत की और उसके जो नतीजे आए, वह भी सबके सामने है। पार्टी के भविष्य के बारे में निर्णय लेते समय खुद कमलनाथ और राष्ट्रीय नेतृत्व को इन तमाम बातों का ख्याल रखना चाहिए।

3. संगठन जस का तस, कमलनाथ संयोजक, सिंधिया प्रचार अभियान प्रमुख, मुख्यमंत्री का फैसला बाद में

पार्टी के प्रदेश महामंत्री रह चुके एक नेता सत्याग्रह से बातचीत में तीसरी संभावना यह बताते हैं कि कमलनाथ को प्रदेश में संयोजक जैसी कोई जिम्मेदारी दे दी जाए क्योंकि इस वक्त वही एक ऐसे नेता हैं जिसके नाम पर सभी नेता एकजुट हो सकते हैं। वे कहते हैं, लेकिन दूसरी बात यह भी सही है कि बढ़ती उम्र के कारण वे बहुत मेहनत कर पाएंगे, इसमें संदेह होना लाजिमी है। लिहाजा, सिंधिया को प्रचार अभियान की कमान सौंपी जा सकती है। वहीं, अरुण यादव प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपना काम करते रहें। इनके बीच समन्वय/संयोजन का जिम्मा कमलनाथ को सौंपा जा सकता है क्योंकि उनके पास इस तरह के काम का अनुभव खूब है। वे आगे कहते हैं, जहां तक मुख्यमंत्री पद की बात है तो इसका फैसला चुनाव में पार्टी की जीत के बाद ही लिया जाना चाहिए। इससे पहले यह घातक हो सकता है।

4. नाथ और सिंधिया की दावेदारी के बीच दिग्विजय और अरुण यादव की भूमिका

प्रदेश नेतृत्व में परिवर्तन की इन अटकलों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के भविष्य पर भी बात होना लाजिमी है। सो, जैसा कि प्रदेश के एक नेता सत्याग्रह से बातचीत में कहते है, इन दिनों दिग्विजय सिंह की मांग राज्य की राजनीति में कम होती जा रही है। यहां तक कि पिछले उपचुनावों में पार्टी के प्रत्याशियों तक ने उन्हें प्रचार के लिए अपने क्षेत्र में बुलाने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। ऐसे में यही मानकर चलना चाहिए कि वे केंद्र में रहेंगे। दिग्विजय सिंह के खेमे के समझे जाने वाले एक अन्य नेता भी थोड़ी झिझक के साथ यह मान लेते हैं। लेकिन साथ में यह भी जोड़ते हैं कि प्रदेश में पार्टी का नेतृत्व जो भी संभालेगा, उसे मजबूती देने का काम दिग्विजय करते रहेंगे।

रही बात मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव की, तो खबरों के मुताबिक, उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से अपने लिए कुछ समय मांग लिया है। यह उन्हें शायद मिल भी गया है। बीते शनिवार को राज्य कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता केके मिश्रा ने मीडिया को बताया, प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की है। गांधी ने उनसे कहा है कि वे अपनी जिम्मेदारी निश्चिंत होकर पहले की तरह निभाते रहें। जानकारी के मुताबिक, नेतृत्व से मिले इस आश्वासन के बाद यादव प्रदेश के विभिन्न अंचलों के दौरे पर भी निकल गए हैं। हालांकि, फिर भी खुद उनके समर्थक मान रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन तो होगा। क्योंकि वजहें चाहे जो रही हों, नेतृत्व की अपेक्षाओं पर यादव पूरी तरह खरे नहीं उतर सके हैं। लेकिन चूंकि वे राहुल गांधी के विश्वस्त हैं, इसलिए उन्हें केंद्र में ठीक-ठाक भूमिका ही मिलेगी। (सत्याग्रह)

धर्म, कला-संस्कृति और सौंदर्य की चादर से ढकी धर्मशाला

(पेज 9 से आगे)

अनेक प्राचीन मंदिर जैसे ज्वालामुखी मंदिर, ब्रजेश्वरी मंदिर और चामुंडा मंदिर बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। धर्मशाला के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों के अंतर्गत काँगड़ा आर्ट म्यूजियम (कला संग्रहालय), सेंट जॉन चर्च और वॉर मेमोरियल (युद्ध स्मारक) शामिल हैं। इसके अलावा कोतवाली बाजार इस स्थान का जाना माना शॉपिंग केंद्र (खरीददारी केंद्र) है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहां घनी आबादी के बीच स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान जिसे ऊँची पहाड़ियों से सैलानी देखकर आश्चर्यचकित होते हैं क्योंकि क्रिकेट मैदान एक पृथक पहाड़ी के मध्य बनाया गया है। धर्मशाला से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इन्द्रू नाग पर्यटकों के विशेष आकर्षण का केंद्र है क्योंकि यहां से धौलाधार पर्वत चोटियां काफी करीब नजर आती है साथ ही पैराग्लाइडिंग के शौकीन इस जगह पर खतरों से लड़कर रोमांच का नया-नया अनुभव लेते हैं। इसके अतिरिक्त चाय बागान, चीड के जंगल और देवदार के पेड़ इस स्थान के आकर्षण को बढ़ाते हैं। काँगड़ा घाटी में स्थित गग्गल हवाई अड्डा धर्मशाला का निकटतम हवाई अड्डा है जो 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हवाई अड्डा नई दिल्ली हवाई अड्डे से घरेलू उड़ानों द्वारा जुड़ा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय यात्री दिल्ली से गग्गल के लिये जुड़ी हुई उड़ान ले सकते हैं। धर्मशाला का निकटतम रेलवे स्टेशन काँगड़ा मंदिर है जो 22 किमी की दूरी पर स्थित है। हालांकि सभी ट्रेन यहाँ नही रुकती क्योंकि यह एक छोटा स्टेशन है। धर्मशाला का निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन पठानकोट है जो 85 किमी की दूरी पर स्थित है। पठानकोट रेलवे स्टेशन भारत के सभी प्रमुख स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। वे यात्री जो रास्ते द्वारा यात्रा करना चाहते हैं वे धर्मशाला के पास के शहरों से निजी या राज्य परिवहन की बसों का उपयोग कर सकते हैं। धर्मशाला में गर्मी का मौसम मार्च से जून के बीच रहता है। हिमाचल की शीतकालीन राजधानी को काफी करीब से देखने के बाद मैं और प्रकाश बादल अगले पड़ाव की ओर निकल पड़े।

पेज 7 से आगे

प्रबंधन कौशल के तीन वर्ष

चाहे वह डिजिटल लेनदेन हो या ई वी एम हो। डिजिटल भुगतान हेतु कोई आपको बाध्य नहीं कर रहा है, किंतु जब बैंक और इनके द्वारा संचालित एटीएम कैश की कमी से जूझ रहे हों, कैश लेनदेन पर अनेक प्रकार के कर लगाए जा रहे हों और टैक्सेस का विवरण ऐसे फॉर्मेट्स में माँगा जा रहा हो जो डिजिटल एकाउंटिंग को सपोर्ट करते हों तो डिजिटल ट्रांसैक्शन आपके लिए बाध्यकारी हो जाता है। लेकिन चर्चा आपको डिजिटल ट्रांसैक्शन की ओर धकेलने की नहीं भीम, आधार पे आदि का उपयोग करने वाले और लाटरी जीत कर डिजिटल लेनदेन के माध्यम से अपनी तकदीर चमकाने वाले लोगों की हो रही है जो सकारात्मक सोच वाले मीडिया को करनी भी चाहिए। चाहे स्मार्ट सिटी हो चाहे स्मार्ट रेलवे स्टेशन हों कॉर्पोरेट्स ही देश का भविष्य बना रहे हैं। रेल मंत्री और किसी कॉर्पोरेट कंपनी के सीईओ की कार्यप्रणाली में यदि कोई अंतर है तो वह नीतियों के क्रियान्वयन की विधि में है, कॉर्पोरेट बॉस जो डंके की चोट पर कर रहे हैं, रेलमंत्री वही पिछले दरवाजे से नजर बचाकर कर रहे हैं। जनता के छोटे-छोटे त्यागों से देश बदल रहा है। जनता खुशी-खुशी रसोई गैस की, रेल टिकट की और भी तरह तरह की सब्सिडी छोड़ रही है। जनता और उसके लोकप्रिय प्रधानमंत्री के बीच मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से सीधे संवाद हो रहा है। आत्मपीड़क धर्मभीरु भारतीय नागरिक के अवचेतन में प्रवेश कर चुके त्याग के विचार को कॉर्पोरेट हितों की पूर्ति हेतु प्रयुक्त किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार देश की व्यवस्था के रग-रग में व्याप्त है। सार्वजनिक जीवन में रहने वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति न होगा जिससे अपने जीवन के किसी मोड़ पर भ्रष्टाचार की भेंट न हुई होगी। यदि दोनों में मित्रता न हुई हो तो एक-दूसरे का विरोध न करने की संधि तो अवश्य हुई होगी। पूर्ववर्ती सरकारों के भ्रष्ट नेताओं ने वर्तमान सरकार को भ्रष्टाचार का इतना मसाला दे दिया है कि उसके उपयोग से वह अपनी भ्रष्टाचार विरोधी छवि की रक्षा और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का भयादोहन सरलतापूर्वक कर सकती है। बारंबार स्वयं को भ्रष्टाचारमुक्त और भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस रखने वाली सरकार का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। अनेक अनोखे तर्क विमर्श में हैं जिनमें एक यह भी है कि अविवाहित और परिवार त्यागी व्यक्ति आखिर किस लिए भ्रष्टाचार करेंगे। अथवा देश में पहली बार हिन्दू धर्म की विजय पताका फहराने वाला सशक्त नेता सत्ता में है, उसका विरोध किया तो आजीवन बहुसंख्यक होने के बावजूद अल्पसंख्यक की भांति रहना होगा। नोट बंदी और डिजिटल इकॉनॉमी आम नागरिक के लिए भ्रष्टाचार के अवसर कम करने के उपाय हैं किंतु नॉन परफार्मिंग एसेट्स की रीस्ट्रक्चरिंग तो वह अनूठी सूझ है जो कॉर्पोरेट्स की सहूलियत के लिए गढ़ी गई है।

देशवासियों को स्वच्छ, सभ्य एवं अनुशासित बनाने के लिए शौचालय, रसोई गैस के कनेक्शन और ढेर सारे आर्थिक नियंत्रण के नियमों का अभ्यस्त बनाया जा रहा है। भूख, गरीबी, बेकारी, बीमारी, कुपोषण, अशिक्षा जैसे आउटडेटेड मुद्दों का स्थान नई चुनौतियों ने लिया है-जन धन खातों को आधार से कैसे जोड़ें, अपने स्मार्ट मोबाइल पर गैस सब्सिडी के अलर्ट कैसे प्राप्त करें, श्रमिक स्वयं को आधार से कैसे जोड़ें आदि आदि। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध न करा पाने वाले देश में प्रति फ्लश 13 लीटर पानी की आवश्यकता रखने वाले शौचालय बिना सीवर सिस्टम के बन रहे हैं, चल रहे हैं और ग्राम ओडीएफ घोषित हो रहे हैं, यह किसी करिश्मे से कम नहीं है। छतविहीन झोपड़ियों में उज्ज्वला योजना के सिलिंडर शोभायमान होकर यह सिद्ध कर रहे हैं कि अब रेडियो और टीवी के विज्ञापनों की दुनिया का अवतरण हर घर में हो गया है।

मनरेगा के तालाबों में जल लबालब भरा हुआ है बस इसे देखने के लिए किसी भ्रष्टाचारी की नजर चाहिए। फील गुड फैक्टर तब तो साकार न हो पाया था पर अब हो गया है। हिन्दूवादी शक्तियाँ इस प्रत्याशा में हैं कि आततायी आक्रांताओं के प्रतीकों का ध्वंस होकर नए मंदिर, नए स्मारक, नए नाम और नया इतिहास रचा जाएगा। अडानी और अंबानी जैसे कॉर्पोरेट्स इस प्रत्याशा में हैं कि जन प्रतिरोध को शून्य कर देश की अर्थव्यवस्था थाली में सजाकर उनके सम्मुख पेश कर दी जाएगी। निर्धन इस प्रत्याशा में हैं कि उनकी निर्धनता पर दया कर सरकार उदारतापूर्वक उन्हें दान देती रहेगी और उनकी निर्धनता को जीवित रखेगी। सवर्ण इस प्रत्याशा में हैं कि उनका स्वर्ण युग लौटेगा और आरक्षण का अंत होगा। दलित यह सोच बैठे हैं कि चुनाव जीतकर सत्ता सुख भोगनेवाले और आरक्षण का लाभ ले उच्च पदों पर बैठे उनके स्वजन ही जब ब्राह्मणवादी सोच का शिकार हो जाते हैं तो घोषित ब्राह्मणवादी कौन से बुरे हैं? मुस्लिम यह सोच रहे हैं कि धर्म की सर्वोच्चता की आड़ में जो मुट्ठी भर लोग सारे लोगों पर हुकूमत कर उनका दमन करते हैं उन्हें सबक सिखाने के लिए हिन्दू वादी शक्तियों की मदद लेना ही उत्तम कूटनीति है।

देशभक्त एक युद्ध चाहते हैं और जमाखोर और मुनाफाखोर इनके सुर में सुर मिला रहे हैं क्योंकि युद्ध होगा तो महंगाई, गरीबी और अराजकता फैलेगी और इनके दिन बहुरेंगे। प्रधानमंत्री जीवित किंवदंती में बदलते जा रहे हैं। देश में जो कुछ अच्छा हुआ है और जो कुछ अच्छा होगा वह उनके अतिमानवीय बल्कि दैवीय गुणों के कारण हुआ है एवं होगा। अब विरोध शब्द ही अर्थहीन और अप्रासांगिक हो गया है। आइए बाहुबली 2 क्या देखते हैं, साक्षात चमत्कार को घटित होते देखिए।

महाराष्ट्र में सड़क हादसा, 7 मरे

अहमदनगर, 24 मई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र में धांगरवाड़ी के पास बुधवार तड़के एक तेज रफ्तार बोलेरो के डिवाडर से टकराने और फिर सामने से आ रहे ट्रक से हुई जोरदार भिड़ंत में सात लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास आयोग (एमआईडीसी) पुलिस स्टेशन के विलास कानावाड़े ने बताया कि हादसा तड़के करीब चार बजे व्यस्त अहमदनगर-औरंगाबाद राजमार्ग पर हुआ। बोलेरो औरंगाबाद की ओर जा रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि वाहन के चालक को झपकी आ गई थी और उसने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद यह डिवाइडर से टकरा गई और सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराई। ट्रक अहमदनगर की ओर जा रहा था। वाहन में सवार सभी यात्री गहरी नींद में थे, जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। कानावाड़े ने बताया, दुर्घटना बहुत भयानक थी। फिलहाल किसी शव की पहचान नहीं हो पाई है और न ही यह पता लग पाया है कि वे कहां जा रहे थे और कहां से आ रहे थे? पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश कर रही है।